दो एकड़ से अधिक के मालिक उद्योगों को बेच सकेंगे जमीन

- जिला अधिकारी करेंगे सूचीबद्ध

संवाददाता ▷ पटना

उद्योग विभाग ने प्रदेश में औद्योगिक भूमि की कमी को देखते हुए आम लोगों से जमीन जुटाने की नीति बना रहा है. इस रणनीति के तहत वह राज्य के लोगों से उद्योगों के लिए अपने स्तर से जमीन बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगा. खासतौर पर उद्योग विभाग ऐसे भू स्वामियों से जमीन चाहता है, जिनके पास दो एकड़ से अधिक जमीन है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बनायी जा रही नयी नीति में किसानों या भू स्वामियों को अधिकार होगा कि वह खुद अपनी जमीन की कीमत तय करें. हालांकि, इस संबंध में किसानों को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि विक्रय मूल्य निबंधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि तक के लिए एक मान्य होगा. उद्योग विभाग की तरफ से बनायी जा रही पॉलिसी में भू स्वामियों को ऐसी भूमि बेचने से पहले जिला अधिकारी के यहां सूचीबद्ध करानी होगी.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ऐसी जमीन की मिल्कियत/ विवादमुक्त होने की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगा.तभी वह

जमीन बेची जा सकेगी. बेचने की प्रक्रिया भी तय की गयी है. जिला प्रशासन इस तरह की जमीन को बियाडा को भेजेगा. बियाडा को इस तरह की जमीन अपलोड करनी होगी. जानकारों के मुताबिक बियाडा सभी निवेशकों को विभिन्न माध्यमों से सूचित करेगा. अगर पूंजी निवेशक पंजीकृत भूमि पर निवेश करते हैं तो स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में सौ फीसदी की निर्धारित छूट दी जायेगी. इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी निवेशक को मिल सकेंगे.

गौरतलब है कि उद्योग विभाग ने नयी औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भू अर्जन और सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ये योजना बनायी गयी है. उल्लेखनीय है कि ये पॉलिसी बन कर तैयार है. कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसे घोषित किया जायेगा.

Hindustan (Date: - 23/12/2019)

बैठक में निर्णय

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार में गन्ना के मूल्य में चालू पेराई सत्र में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। पिछले वर्ष की ही दर पर ही गन्ने की खरीद चीनी मिलों द्वारा की जाएगी। रविवार को गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार सुगर मिल्स एसोसिएशन (बीएसएमए) के शिष्टमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके पूर्व 25 नवंबर 2019 को पेराई सत्र 2019-20 के गन्ना मूल्य निर्धारण को बीएसएमए के शिष्टमंडल की बैठक गन्ना मंत्री बीमा भारती की अध्यक्षता में हुई थी।

बीएसएमए द्वारा जारी सूचना के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से मिलों को पिछले पेराई सत्र 2018-19 में हुए भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद गन्ने की खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले पेराई सत्र के गन्ना मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई है। बैठक में बीएसएमए प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि उनकी पेराई सत्र 2019-20 के लिए अनुदान मांग पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, ताकि समय से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान संभव हो सके। इस पर अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में क्षेत्रिय विकास परिषद कमीशन की दर कुल गन्ना मूल्य के 0.75 फीसदी में से सरकार द्वारा 0.55 फीसदी के अनुदान के बाद 0.20 फीसदी देय होगा। जीएसटी लागू होने के बाद क्रय कर को समाप्त कर दिया गया है। एसोसिएशन ने किसानों से अपील की कि केवल स्वच्छ एवं जड़ पत्ती अगोला रहित गन्ना ही मिल में लाएं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में उत्तर प्रजाति के गन्ने की बुआई कर अधिक उपज लेते हुए आर्थिक लाभ उठाने की सलाह दी।

जस की तस

- 2018-19 की दर से ही 2019-20 में होगी गन्ने की पेराई
- अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग व शुगर मिल्स एसो. की बैठक में निर्णय

25 नवंबर को भी गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक आयोजित हुई थी

स्वच्छ, ताजा एवं जड़पत्ती रहित

गन्ना	मूल्य
उत्तम प्रजाति	310 रुपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रजाति	290 रुपये प्रति क्विंटल
निम्न कोटि	265 रुपये प्रति क्विंटल

निर्धारित मूल्य से 20 रुपये प्रति क्विंटल कम भुगतान होगा

बाह्य केंद्रों पर खरीदे गए सभी कोटि के प्रभेदों पर निर्धारित मूल्य से 20 रुपये प्रति क्विंटल कम भुगतान होगा। साथ ही गन्ना प्रजाति बीओ-110, सीओएस-8436 एवं सीओपी- 98224 की सिर्फ खूंटी वर्तमान सत्र में मिलों द्वारा खरीदी जाएगी, क्योंकि अगले पेराई सत्र 2020-21 से मिलों द्वारा इन प्रभेदों की खरीद नहीं की जाएगी।

Hindustan (Date: - 23/12/2019)

पटना। राजधानी में अगले साल मार्च से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी। केन्द्र ने राज्य सरकार को 25 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला है। एक माह के अंदर टेंडर फाइनल हो जाएगा।

परिवहन निगम की योजना है कि हर हाल में मार्च तक इलेक्ट्रिक बस को सड़कों पर उतार दिया जाए। बिहार में काफी विलंब से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। नई दिल्ली व कोलकाता में इलेक्ट्रिक बसें कई साल पूर्व से ही चल रही हैं। केन्द्र सरकार डीजल बसों की जगह पर इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन पर जोर दे रही है। इसलिए केन्द्रीय योजना के तहत ये इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हो रही है। केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्रालय इसका नोडल विभाग है। बसों की खरीदारी में केन्द्र सरकार सहयोग कर रही है। बसों की खरीद में केन्द्र सरकार 40 प्रतिशत अनुदान देगी। 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वहन करना होगा। एक बस की कीमत एक करोड़ के आसपास है।

इलेक्ट्रिक बसों को रिचार्ज करने के लिए राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। परिवहन निगम के डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बस दो घंटे में चार्ज हो जाएगी। एक बार चार्ज होने पर बस 150 किलोमीटर तक चल सकती है।

Hindustan (Date: - 23/12/2019)

पटना सिटी | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

रविवार की अहले सुबह साढ़े चार बजे भजन-कीर्तन करते श्रद्धालुओं का जत्था प्रभातफेरी में शामिल हुआ। ठंड के बावजूद दर्जनों श्रद्धालु पंज प्यारों की अगुआई में तख्त साहिब से निकल कर अशोक राजपथ होते हुए गायघाट स्थित बड़ा गुरुद्वारा पहुंचे, जहां से वाहन के जरिए पटना जंक्शन तक गए। प्रभातफेरी में पंजाब से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। प्रभातफेरी का नेतृत्व सरदार इन्द्रजीत सिंह बग्गा, दर्शन सिंह, प्रेम सिंह ने किया। सोमवार की सुबह प्रभातफेरी कंगन घाट जाएगी।

ग्यारह दिनों तक चलने वाली प्रभातफेरी में काफी संख्या में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी शिरकत करेंगे। प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह दो जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं एक जनवरी को गायघाट से नगर कीर्तन निकाला जाएगा।

काम में तेजी लाने का निर्देश, टेंट सिटी में बने तीन लंगर पंडाल : दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंहजी के 353वें प्रकाशोत्सव के मौके पर पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कवायद जारी है। रविवार को एसडीओ राजेश रौशन ने कंगन घाट में बन रही टेंट सिटी का मुआयना किया। उन्होंने निर्माण की गति धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए एजेंसी के कर्मियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। एजेंसी के लोगों का कहना है कि यातायात की समस्या के कारण यूपी से कुछ सामान नहीं आ पाए हैं। शीघ्र ही सामान को मंगाकर काम पूरा कर लिया जाएगा। एसडीओ ने श्रद्धालुओं के आवासन, यातायात का रूट प्लान, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा, अनवरत बिजली व पानी की आपूर्ति, चौबीसों घंटे सफाई आदि मुद्दों को लेकर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि कंगन घाट में टेंट सिटी का निर्माण तेजी से कराने का निर्देश दिया गया है। निर्माण में लगी एंजेंसी को चौबीस दिसंबर तक टेंट सिटी तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा स्कूलों में श्रद्धालुओं के आवासन स्थल की रंगाई-पुताई व अन्य सुविधाओं को पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क मरम्मत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी प्रीतेश्वर प्रसाद ने भी तैयारियों का जायजा लिया।

4.30 बजे सुबह पटना सिटी में निकाली गई प्रभातफेरी

प्रकाशोत्सव को लेकर कंगन घाट में बन रही टेंट सिटी को अंतिम रूप देते कलाकार।

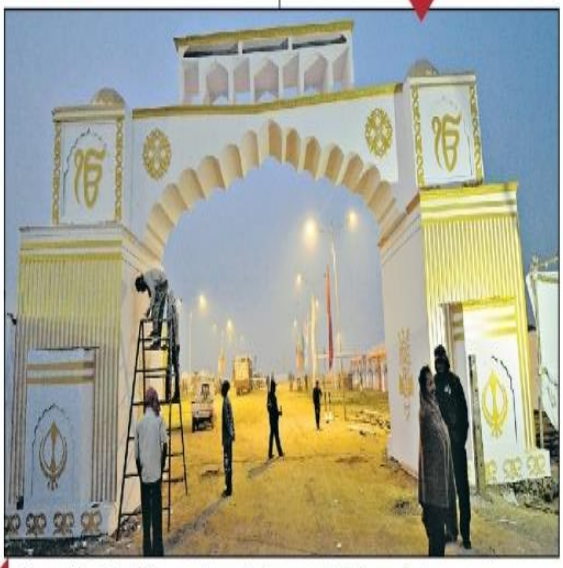

श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव को लेकर प्रभातफेरी निकालती संगत।